भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4274

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता घटक कार्यक्रम योजना

4274. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता घटक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान आवंटित निधि का उपयोग देश की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान अप्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ): क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता घटक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित बजट में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 से अलग बजट प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति मदों में आवंटित, जारी और अप्रयुक्त धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	आवंटन	जारी किया	अप्रयुक्त निधि
2021-22	1,655.03	1,597.56	57.47
2022-23	1,722.54	1,808.86	0.0
2023-24	1,735.36	1,733.19	2.17
2024-2025	1,732.86	1,732.86	0.0

(घ): विभिन्न सिफारिशों और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, एनएसएपी के पुनरुद्धार के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड में संशोधन, सहायता की दर और राज्यों के साथ साझाकरण व्यवस्था शामिल थी, जिसे 15वें वित्तीय आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी की निरंतरता के दौरान विचार किया गया। हालांकि, सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। एनएसएपी के अंतर्गत वार्षिक समग्र बजट परिव्यय, लाभार्थियों की कुल संख्या और सहायता दर के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

*****